

सरकारी जमीन हड़पने का खेल, पुलिस को पुनः जांच के आदेश

स्वास्तिक बिल्डर्स बेनकाब: अदालत ने पुलिस को लगाई फटकार

खारिजी रिपोर्ट पर अदालत ने लगाया ब्रेक

भूमिफिया के कब्जे में सरकारी जमीन

करोड़ों का कॉम्प्लेक्स खड़ा, राजस्व विभाग की मिलीमगत उजागर

सरकारी जमीन को हड़पकर मेसर्स स्वास्तिक बिल्डर्स और भूमिफियाओं ने जो खेल रचा, वह अब अदालत की सख्ती से खुलकर सामने आ गया है। अपराध क्रमांक 136/17 में पुलिस द्वारा दाखिल की गई खारिजी रिपोर्ट को न्यायालय ने पूरी तरह असंगत करार देते हुए निरस्त कर दिया और दोबारा जांच का आदेश दिया। यह मामला न केवल राजस्व की भारी हानि का है, बल्कि भूमिफियाओं और राजस्व विभाग की मिलीमगत से खड़ी की गई षड्यंत्र की गंभीरता का भी है।

शहडोल।

जिले में सरकारी भूमि को फर्जी नामांतरण और जालसाजी कर बेच देने के मामले ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 136/2017 के तहत मेसर्स स्वास्तिक बिल्डर्स के जिम्मेदारों पर आरोप था कि उन्होंने ग्राम भुईबांध स्थित खसरा नंबर 1/176, रकबा 0.387 हेक्टेयर शासकीय भूमि को फर्जी नामांतरण कर कब्जे में ले लिया और आगे करोड़ों रुपये में बेच डाला। पुलिस ने इस पर खानापूरी करते हुए खारिजी प्रतिवेदन (क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल कर मामला दवाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि रिपोर्ट में न तो मूल दस्तावेजों का अध्ययन किया गया और न ही संलग्न अभिलेखों का परीक्षण। न्यायालय ने पुलिस को लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई और पुनः जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

1978 से शुरू हुआ घपला

भूमि घोटाले की जड़ें चार दशक पुरानी हैं। वर्ष 1978 में किशोरीलाल सरावगी को कब्जे के आधार पर भूमि स्वामी घोषित किया गया। इसके बाद महेंद्र सरावगी और उनके पुत्र अनंत सरावगी ने खुद को किशोरीलाल का फर्जी वारिस बताकर नामांतरण का शौच किया। जब नामांतरण की फाइल कलेक्टर के पास पहुंची, तो पिता का नाम ही बदल दिया गया।



असल में खरीदी गई जमीन मात्र 35 डिस्मल थी, लेकिन राजस्व अधिकारियों की मिलीमगत से 65 डिस्मल सरकारी भूमि को जोड़कर विक्रय नामे में 100 डिस्मल दर्ज कर दिया गया। यही से फर्जीवाड़े की इमारत खड़ी हो गई।

कॉम्प्लेक्स खड़ा कर बेचे प्लैट और दुकानें

एक दशक पहले इस जमीन पर प्लैट और दुकानों की बिक्री शुरू हुई। विक्रय अनुमति के नाम पर किसी अन्य भूखंड के दस्तावेज लगाए गए और सरकारी जमीन पर बने बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स को धड़ल्ले से बेच दिया गया। यही नहीं, आसपास की अन्य जमीनों पर भी दबाव दिखाते हुए अवैध कब्जे कर लिए गए। शिकायतकर्ता दिनेश दीक्षित और कई गवाहों ने अदालत में बताया कि पुलिस ने न तो उनके बयान गंभीरता से लिए और न ही

भूमिफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की।

साक्षियों की अनदेखी और पुलिस की मिलीमगत

मामले में साक्षी राकेश मिश्रा और श्यामसुंदर चौधरी जैसे गवाहों ने बयान दिया कि पुलिस ने जानबूझकर उनकी गवाही की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि स्वास्तिक बिल्डर्स और भूमिफिया गिरोह ने न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा कर कॉम्प्लेक्स बनाया बल्कि शिकायतकर्ताओं को लगातार धमकियां भी दी गईं। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

अब बिल्ली के शिकंजे में चूहा

इस पूरे मामले को लेकर बीते एक दशक से चूहे-बिल्ली जैसा खेल चलता रहा। कभी एफआईआर दर्ज हुई, तो कभी खारिजी रिपोर्ट लगाकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब शिकायतकर्ता ने आपत्ति उठाई, तो खारिजी आवेदन रद्द कर दिया गया। बाद में पुनः जांच का आदेश हुआ, लेकिन कमिश्नर स्तर पर सेंटिंग कर केस दवाने की कोशिश की गई। अब अदालत ने एक बार फिर खारिजी रिपोर्ट निरस्त कर

एफआईआर को जीवित कर दिया है।

राजस्व विभाग की भूमिका संदिग्ध

शिकायतकर्ता का साफ आरोप है कि इस पूरे खेल में राजस्व विभाग के अधिकारियों की सीधी मिलीमगत रही। बिना अधिकारियों की मदद के न तो फर्जी नामांतरण संभव था और न ही सरकारी जमीन को विक्रय नामे में जोड़ना। अदालत ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मूल दस्तावेजों और उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा दिए गए आदेशों का अवलोकन किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है।

अब पुलिस की परीक्षा-कब होगी कार्रवाई?

न्यायालय ने आदेश दिया है कि पुलिस दोबारा जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करे। सवाल यह है कि क्या पुलिस मेसर्स स्वास्तिक बिल्डर्स के जिम्मेदारों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करेगी या एक बार फिर भूमिफियाओं की ताकत के आगे नतमस्तक हो जाएगी? यदि यह साबित होता है कि सरकारी जमीन को फर्जी नामांतरण कर बेचा गया है, तो यह केवल राजस्व हानि का मामला नहीं बल्कि भूमिफिया गिरोह का बड़ा नेटवर्क उजागर करेगा। अदालत का आदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है और अब देखा होगा कि स्वास्तिक बिल्डर्स और उनके संरक्षकों पर आखिरकार कब तक शिकंजा कसा जाता है।

विश्वविद्यालय में रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस तकनीक पर व्याख्यान

शहडोल। पं. शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में भूगोल परिषद द्वारा रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस तकनीक विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमरकंटक विश्वविद्यालय के प्रो. चंद्रमौली ने कहा कि वर्तमान समय में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग शिक्षा, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, जलवायु परिवर्तन सहित लगभग प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से हो रहा है। यह तकनीक पृथ्वी को गहराई से समझने का अवसर देती है।

प्रधानमंत्री एक्सिलेंस कॉलेज, बुढ़ार के डॉ. एस.एम. प्रजापति ने जीआईएस तकनीक को आधुनिक युग में निर्णय लेने का सबसे सशक्त साधन बताया। उन्होंने कहा कि यह न केवल पृथ्वी की जटिलताओं को समझने में मदद करता है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की



परिसर प्रभारी प्रो. गीता सराफ ने की। उन्होंने कहा कि भूगोल विभाग समय-समय पर नवाचारपूर्ण गतिविधियों का आयोजन करता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन संस्था में किए गए तीन माह के डेजटेशन कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह कार्य भूगोल विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. सौरभ शिवा के निदेशन में पूरा हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मुनीश सिंह ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. सौरभ शिवा ने किया। इस अवसर पर विभाग के अजय सिंह पटेल, दिलीप मिश्रा, दीपेश पारस, पुष्पा साहू सहित अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे।

एसडीएम ने किया शाला मलियागुड़ा का औचक निरीक्षण

उमरिया। जिले के बिरसिंहपुर पाली विकास खण्ड एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह ने माध्यमिक शाला मलियागुड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति पंजी देखी और कक्षाओं में पहुँचकर बच्चों से पठन-पाठन, गणवेश तथा मध्याह्न भोजन संबंधी जांचकरी ली।



कक्षा 6वीं के बच्चों से पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पाकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण में पाया गया कि शिक्षक बच्चों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे शैक्षणिक स्तर संतोषजनक है। एसडीएम ने बच्चों को नियमित

अध्ययन करने, घर पर अभ्यास जारी रखने और मन लगाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि मेहनत व लगन से पढ़ाई कर अच्छे अंक प्राप्त करें और गांव, स्कूल, जिला तथा प्रदेश का नाम रोशन करें।

शहडोल में शासकीय मुलाजिम असुरक्षित वन विभाग की टीम पर हमला, सर्च वारंट फाड़ा



शहडोल। जिले में माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे शासकीय मुलाजिमों पर खुलेआम हमला बोल रहे हैं। जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र के महदेवा गांव में वन विभाग की टीम पर उस समय हमला किया गया जब वे अवैध रूप से रखी गई इमारती लकड़ी जल्ल करने पहुंचे। आरोपी न केवल टीम से भिड़ गए बल्कि सामने ही सर्च वारंट फाड़ डाला और अधिकारियों के साथ गाली-गलौज कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई।

वन विभाग की टीम पर हमला

जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के महदेवा गांव में वन विभाग की सूचना मिली कि अवैध रूप से जंगलों से काटी गई इमारती लकड़ियों का बड़ा जखीरा छुपाकर रखा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निदेश पर बनी संयुक्त टीम ने मौके पर छापा मारा। जांच में यह पाया गया कि आरोपी सुरेंद्र यादव के घर और बाड़ी के पास लकड़ियां बड़ी मात्रा में छुपाकर रखी गई थीं। जब टीम घर के अंदर तलाशी लेने गई तो आरोपी ने सर्च वारंट मांगा। अधिकारियों ने जैसे ही वारंट दिखाया, सुरेंद्र यादव ने दस्तावेज को वहीं फाड़ दिया और अन्य परिजनों के साथ मिलकर टीम पर हमला बोल दिया।

अधिकारी बने निशाना, महिलाएं भी मिर्झी

बीट गार्ड सूर्य प्रताप सिंह ने शिकायत में कहा कि आरोपी ने न केवल वारंट फाड़ा बल्कि टीम को गाली-गलौज कर धमकाने लगा। इस दौरान घर की महिलाएं भी आक्रामक हो गईं और अधिकारियों को घेरकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि वन विभाग की टीम को अधूरी कार्रवाई छोड़कर थाने लौटना पड़ा। यह घटना साफ दर्शाती है कि अवैध कारोबारियों के सामने शासकीय अमले की स्थिति कितनी कमजोर हो चुकी है।

मामला दर्ज, आरोपी फरार

थाना प्रभारी जयसिंहनगर अजय कुमार बैगा ने बताया कि बीट गार्ड की शिकायत पर आरोपी सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, बाबूलाल और दो अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, गाली-गलौज और शासकीय दस्तावेज को नुकसान पहुंचाने का अपराध दर्ज किया गया है। हालांकि सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

माफियाओं के बढ़ते हौसले

यह पहली बार नहीं है जब जिले में शासकीय मुलाजिमों पर हमला हुआ हो। हाल के वर्षों में अवैध कारोबारियों और माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी रेत माफिया तो कभी लकड़ी माफिया आए दिन सरकारी कर्मचारियों पर हमला कर प्रशासन की नाक में दम कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब सरकारी मुलाजिम ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता न्याय और सुरक्षा की उम्मीद किससे करे।

शहडोल में नेशनल लोक अदालत, 2408 प्रकरणों का हुआ निराकरण

शहडोल

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निदेश पर शहडोल सहित ब्योहारी, बुढ़ार एवं जयसिंहनगर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काशीनाथ सिंह ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। प्रकरणों के निराकरण के लिए जिलेभर में 20 खंडपीठ गठित की गईं। लोक अदालत में कुल 2408 प्रकरणों का निपटारा किया गया, जिनमें 791 लंबित एवं 1617 प्री-लिटिगेशन प्रकरण शामिल रहे। इन मामलों में 2 करोड़ 62 लाख 58 हजार 949 की राशि का अवाई पारित हुआ। विशेष रूप से मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, आपराधिक राजीनामा योग्य, वैवाहिक विवाद तथा विद्युत विभाग से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया।



जिला न्यायालय परिसर में विद्युत विभाग, नगरपालिका, बैंक और बीएसएनएल के स्टॉल लगाए गए। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा विधिक सेवा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें नालसा व सालसा की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश द्वय कमलेश कोल, कृष्णपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र सिंह सिंगार, न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपेन्द्र सिंह मडावी, सीता शरण यादव, सुश्री दीपति चेहान, श्रीमती

जिलांतर्गत कोर्ट मोहिर की मासिक बैठक संपन्न

शहडोल। पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 14 सितंबर को पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में कोर्ट मोहिर की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में न्यायालय से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने वारंटों का समय पर तामीली सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से चिन्हित प्रकरणों में वारंटों की तामीली में विलंब को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी मामले में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने में कठिनाई हो रही है, तो संबंधित अधिकारियों को तत्काल अगगत कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी पुलिसकर्मी को न्यायालय में पेशी के दौरान कोई समस्या आ रही है, तो उसकी सूचना समय पर दी जाए। बैठक में जिले के विभिन्न न्यायालयों के कोर्ट मोहिर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रीडर लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, नगर शाखा से सज्जन, सुरेश पाण्डेय एवं आर. भगवानिया उपस्थित रहे। बैठक के दौरान न्यायालय संबंधी प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने और लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

एसडीएम ने खाद-बीज दुकानों का किया औचक निरीक्षण

उमरिया।

जिले के विकास खण्ड बिरसिंहपुर पाली एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह ने पाली स्थित खाद बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर कृषि विभाग द्वारा संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान महामाया बीज भण्डार में दस्तावेजों का व्यवस्थित संघारण नहीं पाया गया। स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर वास्तविक भंडार में पाई गई सामग्री में अंतर पाया गया। टीम ने अव्यवस्थित रखे सामान और खाद के स्टॉक को नोट किया गया। बिरासनी खाद-बीज भंडार में खाद-बीज की बिक्री किराना स्टोर के माध्यम से किया जाना पाया गया, जिस



पर मौके पर ही पंचनामा बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। एसडीओ (कृषि) राशिद खान ने बताया कि अनियमितताओं पर संबंधित फर्मों

को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

सेवारत शिक्षकों की नौकरी पर संकट

शहडोल।

सेवारत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। आदेश के अनुसार, चाहे शिक्षक की नियुक्ति किसी भी वर्ष में हुई हो, सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इस निर्णय से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों शिक्षकों के सामने प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष लालजी तिवारी द्वारा जारी विज्ञापित में बताया गया कि इस नियम के कारण शिक्षकों के बीच गहरी निराशा, भय और असुरक्षा का माहौल है। लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है, वहीं उनके परिवार के भरण-पोषण का सवाल भी खड़ा हो गया है। इसी संदर्भ में शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। यह ज्ञापन कलेक्टर शहडोल के



की अनिवार्यता लागू करना उनके साथ अन्याय है और यह निर्णय उनके परिवारों के भविष्य पर भी शीघ्र असर डाल रहा है। इसलिए वे एकजुट होकर इस नियम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

शिक्षकों का कहना है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा

खबर संक्षेप

वैष्णोदेवी यात्रा के लिए 23 सितंबर तक आवेदन कटनी। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत वैष्णोदेवी यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह यात्रा 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। कटनी जिले के लिए इस यात्रा में कुल 279 बर्थ आवंटित किए गए हैं। यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। वैष्णोदेवी तीर्थयात्रा के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सभी) को यह जिम्मेदारी दी गई है। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, वोटर आईडी या आधार कार्ड की प्रतिलिपि देना अनिवार्य है। 65 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिभा योजना के तहत मिलेगी प्रोत्साहन राशि कटनी। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता अर्जित करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों से जनजातीय कार्य विभाग ने प्रतिभा योजना के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने जेईई मेन या एडवांस, नीट, क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफल होकर आईआईटी, एम्स, एनडीए जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। योजनान्तर्गत जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है, उन्हें 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जबकि जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से 10 लाख रुपये के बीच है, उन्हें 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इच्छुक छात्र एमपीटास पोर्टल पर पंजीयन उपरान्त लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर है।

जिप की सामान्य सभा की बैठक 3 अक्टूबर को कटनी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गोमावत ने इस बैठक में कृषि विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पीआईयू, सहकारी महिला एवं बाल विकास, वन, खनिज, नर्मदा घाटी, उद्योग, प्रधानमंत्री सड़क, सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों और समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 और 11 के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू कटनी। पीएमश्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, बड़वारा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विद्यालय के प्राचार्य आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि इच्छुक और योग्य छात्र इन कक्षाओं में 'लेटरल एंट्री' के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 है। प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

हरवाह ग्राम में कीचड़ से सनी रोड, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान बरही। तहसील अंतर्गत ग्राम हरवाह में कई वर्षों से रोड खराब है बरसात के मौसम में कीचड़ से सन जाती है शंकर मंदिर से लेकर हनुमान मंदिर तक निकलना मुश्किल है स्कूली बच्चों व ग्रामीणों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है पंचायत के जिम्मेदार सरपंच सचिव का इस ओर ध्यान नहीं है की रोड की मरम्मत करावें।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष का हुआ मत्स्य स्वागत



नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी न्यायालय में पेश

शहडोल। जिले के जयसिंहनगर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर विधिकरुद्ध बालक न्यायालय में पेश किया है। मामला 12 सितंबर 2025 का है, जब थाना जयसिंहनगर क्षेत्र की 16 वर्षीय पीड़िता अपने माता-पिता के साथ महिला थाना शहडोल पहुंची और लिखित आवेदन दिया। आवेदन में आरोप लगाया गया कि ग्राम का एक विधिकरुद्ध बालक पिछले कई दिनों से उसके साथ जबरन गलत काम (दुष्कर्म) कर रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। थाना प्रभारी जयसिंहनगर सहित महिला थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिसकर्मियों की सक्रियता से आरोपी को बाल न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मप्र शिक्षक संघ जिला इकाई अनूपपुर की बैठक संपन्न



हरिगुणि न्यूज अनूपपुर। 14 सितंबर को विकास खण्ड जैतहरी इकाई के अनुरोध पर मध्यप्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई अनूपपुर की बैठक शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर कोतलाय में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यता अभियान के अंतर्गत समस्त इकाइयों को दी गई रसीद बंदियों को जमा करने के सम्बन्ध में रखी गई थी। इसमें भरी एवं खाली रसीद बंदियों को राशि एवं सदस्यता सूची के साथ जमा करने का आग्रह पूर्व में किया गया था। बैठक में विकासखंड अनूपपुर जैतहरी पुष्पराजगढ़ नगर इकाई अनूपपुर कोतलाय के सभी सदस्य उपस्थित हुए। बैठक का प्रारंभ मां वीणा वादिनी मां सरस्वती का स्मरण करते हुए सर्व प्रथम संभागीय संगठन मंत्री डॉ नरेन्द्र पटेल ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही दिनांक 15 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने हेतु भारी संख्या में उपस्थित होने के लिए आग्रह किया। बैठक में जनजातीय

कार्य विभाग के प्रदेश संयोजक अनिल कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि जिला अध्यक्ष अतिशीघ्र संभाग कार्यकारिणी को रसीद बंदियों के साथ सूची एवं राज्यांश की राशि शीघ्र भेजें। जिला अध्यक्ष संजय कुमार निगम ने अपने उद्बोधन में बताया कि जिला अंतर्गत जितनी भी शिक्षकीय समस्याएं हैं उससे ब्लॉक इकाई जिले को अवगत करावें जिससे उन समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। कार्यक्रम में संभागीय कोषाध्यक्ष रामकुमार राठौर तहसील अध्यक्ष जैतहरी श्रीमती केशकली राठौर ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन जैतहरी विकासखंड इकाई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के द्वारा किया गया।

रामपुर बटूरा खदान में रोड सेल पर मनमानी वसूली, ट्रांसपोर्टर परेशान

धनपुरी। रामपुर बटूरा खदान में संचालित रोड सेल इन दिनों विवादों में है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि यहां से कोयला उठाने के दौरान उनसे मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। प्रति टुक लगभग 700 रुपए तक अतिरिक्त वसूली की जाती है और इसका एवज में बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला देने की बात कही जाती है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इस व्यवस्था से उनका खर्चा और बढ़ गया है। पहले से ही बड़े डीजल और ऑपरेशन लागत के बीच यह अवैध वसूली उनकी जेब पर भारी पड़ रही है। उनका आरोप है कि प्रबंधन की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है, वरना बिना सहमति के इतनी बड़ी रकम की वसूली संभव नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान में यह सब लंबे समय से जारी है। रोड सेल के नाम पर अच्छा-खासा कमीशन वसूला जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टरों को मजबूरी में पैसा देना पड़ता है। वहीं प्रबंधन की चुप्पी इस पूरे मामले को और संदिग्ध बना रही है। ट्रांसपोर्टरों ने प्रशासन से इस पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि मनमानी वसूली पर रोक लगे और उन्हें राहत मिल सके।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ने सौपा ज्ञापन शराबी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग



शहडोल। जिले के जयसिंहनगर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने सिविल अस्पताल की शर्मनाक घटना को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा। आरोप है कि खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह पटेल ने प्रसूता महिला के परिजनों के साथ शराब के नशे में मारपीट और गाली-गलौज की। पुलिस में शिकायत और एस्पपी तक गृहार लगाने के बावजूद कार्रवाई न होने से आक्रोश बढ़ा और आंदोलन की चेतावनी दी गई।

डॉक्टर ने की मारपीट और अमद्रता
ज्ञापन में बताया गया कि 11 अगस्त 2025 को कन्नड़ी खुर्द निवासी प्रसूता देववती सिंह को प्रसव पीड़ा होने पर सिविल अस्पताल जयसिंहनगर में भर्ती कराया गया। महिला के साथ उसके परिजन हेतराम सिंह, बिहारी सिंह, मुन्नी बाई और अन्य मौजूद थे। आरोप है कि 12 अगस्त को रात करीब 11 बजे अस्पताल में पदस्थ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह पटेल शराब के नशे में 5-6 साथियों के साथ पहुंचे और प्रसूता के परिजनों के साथ मारपीट व गाली-गलौज की।

पुलिस की चुप्पी पर उठे सवाल
पीड़ितों ने घटना की शिकायत तुरंत जैसिनगर थाना में दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 14 अगस्त को पुलिस अधीक्षक शहडोल को लिखित शिकायत

सौंपी गई। बावजूद इसके अब तक डॉक्टर के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस उदासीनता को लेकर परिजनों और स्थानीय नागरिकों में गहरी नाराजगी है।

ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ने एसडीएम जयसिंहनगर के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए। आरोपी डॉक्टर आनंद सिंह पटेल को तत्काल पद से हटाया जाए। अस्पतालों में शराबखोरी और गुंडागर्दी जैसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई हो।

कड़ा कदम उठाने की चेतावनी
ज्ञापन सौंपने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सिविल अस्पताल जैसी संस्थाओं में इस तरह की घटनाएं जनता की आस्था और विश्वास को तोड़ती हैं। ऐसे चिकित्सक स्वास्थ्य व्यवस्था पर कलंक हैं और प्रशासन को कठोर रुख अपनाना होगा।

बाल विवाह समाज के लिए अभिश्राप -महंत अर्जुन दास श्री राम जानकी मंदिर बुढ़ार में बालविवाह मुक्त भारत का संकल्प



शहडोल। गत दिवस राम जानकी मंदिर बुढ़ार में आयोजित हुआ बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प कार्यक्रम। बाल विवाह की रोक-थाम के लिए आजजस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) की सहयोगी संस्था होलिस्टिक एक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्लोबल इंटरफेथ वीकेंड के अंतर्गत बाल विवाह के समाप्त हेतु धर्म गुरुओं से संदेश प्रसारित करने के लिए इस सप्ताहांत यह विशेष अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर रामजानकी मंदिर बुढ़ार के महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज ने संदेश देते हुए कहा कि बाल विवाह हमारे समाज में एक अभिश्राप है। समाज के सभी सजज नागरिकों को एक साथ मिलकर इस कुरीती को समाज से दूर करने के लिए आगे आना होगा।

मैं आह्वान करता हूँ कि सभी इस अभियान में जुड़े और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने में सहयोग करें। कार्यक्रम में रामजानकी मंदिर बुढ़ार के पुजारी चंडिका प्रसाद पाठक, किरण किशोर द्विवेदी की सादर उपस्थिति रही। उक्त आशय की जानकारी देते जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) प्रक्रुष्ठ संस्था के डायरेक्टर शुशील शर्मा ने बताया कि दिनांक 12 से 14 सितंबर 2025 तक इस अभियान के अंतर्गत शहडोल संभाग के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में धर्म गुरुओं के साथ इस कार्यक्रमों को आयोजित कर बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने में विजय द्विवेदी, अजय गुप्ता एवं मुन्ना गुप्ता का विशेष योगदान रहा है। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र त्रिपाठी ने किया।

आदित्य सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल को मिली नई मजबूती एमडी रेडियोलॉजिस्ट डॉ. कौशिक शामिल



शहडोल। यहां 25 बेड का आईसीयू और 6 आधुनिक वेंटिलेटर उपलब्ध है। साथ ही, अस्पताल में न्यूरोसर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर 24x7 सेवाएं दे रहे हैं। इको की सुविधा भी चौबीसों घंटे मौजूद है, जिससे हृदय रोगियों को तुरंत लाभ मिलता है। अस्पताल में मौजूद आधुनिक उपकरण और क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट की विशेष सुविधाएं इसे जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों से अलग पहचान दिलाती हैं। आदित्य हॉस्पिटल की यही विशेषता है कि यह मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देने में हमेशा अग्रणी रहा है। अस्पताल के संस्थापक डॉ. आदित्य द्विवेदी ने इस अवसर पर कहा, शहडोल मेरी जन्मभूमि है और यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना मेरा संकल्प है। हमारा प्रयास है कि जिले के लोगों को बड़े शहरों पर निर्भर हुए बिना, यहीं आधुनिक चिकित्सा सेवाएं मिलें। गौरतलब है कि आदित्य सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल जिले के एकमात्र ऐसा संस्थान है, जिसका रेलवे, कोल इंडिया, एसईसीएल और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ टाईअप है। इसके अलावा, यह अस्पताल सभी बीमा और टीपीए कंपनियों से भी जुड़ा हुआ है। इससे मरीजों को उपचार के लिए वित्तीय सहयोग और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदित्य सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाओं से अब गंभीर बीमारियों के लिए बड़े शहरों की दौड़ कम होगी। जिले के मरीजों को त्वरित जांच और इलाज का भरोसा मिलेगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक तकनीक से लैस यह अस्पताल, शहडोल वासियों के लिए सचमुच एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है।

सामाजिक सेवा की मिसाल बने पार्षद सिल्लू रजक गंभीर रूप से घायल 80 वर्षीय बुजुर्ग को मिला नया जीवन



शहडोल। बंधवाबारा रेलवे स्टेशन पर उपेक्षित और बेसहारा जीवन जी रहे 80 वर्षीय बुजुर्ग शंकर बाबा यादव को स्थानीय समाजसेवियों और पार्षद सिल्लू रजक ने नया जीवन दे दिया। सीढियों के नीचे असहाय हालत में पड़े इस बुजुर्ग को देख कर किसी की भी आंखें भर आतीं। समाजसेवियों ने तुरंत मानवता का परिचय दिया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया और उनके इलाज व देखभाल का जिम्मा उठाया।

तिल-तिल कर टूट रही थी जिंदगी
बंधवाबारा रेलवे स्टेशन की भीड़भाड़ के बीच सीढियों के नीचे शंकर बाबा यादव का जीवन धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के खतघोरा गांव के निवासी शंकर बाबा 24 साल पहले यहां आए और यहीं ठहर गए। पहले वे भिक्षा मांगकर किसी तरह पेट पाल लेते थे, लेकिन कुछ समय पूर्व पुल से गिरने के कारण उनकी दोनों कलाइयों की हड्डियां टूट गईं। चलने-फिरने की ताकत भी जवाब दे गई और वे जल्द प्लास्टर किया जाएगा।

पार्षद सिल्लू रजक की अग्रणी भूमिका
इस नेक कार्य में पार्षद सिल्लू रजक सबसे आगे रहे। उनके साथ प्रिंस विश्वकर्मा, विकास जोतवानी, लकी वर्मा, खुशी सोनी, श्याम बहादुर सिंह और अन्य लोग भी शामिल रहे। इन सभी ने न केवल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया बल्कि यह भी वादा किया कि आगे के इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी वे सामूहिक रूप से निभाएंगे।

समाज के लिए बड़ा संदेश
इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मानवता आज भी जिंदा है। जिस बुजुर्ग ने जिंदगी का लंबा सफर अकेले काटा और अंत में असहाय हो गया, उसके सहारे समाज बना। यह संवेदनशील कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल है। यह संदेश भी साफ है कि बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बनना केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है।





करोड़ों की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र का

हस्तांतरण अटक

अनूपपुर। मेडियारास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेडियारास का निर्माण 295 लाख रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग (मवन) अनूपपुर द्वारा किया गया था। तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य 31 जुलाई को पूर्ण भी कर लिया गया। लेकिन आज दिनांक तक यह मवन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है। निर्माण एजेंसी ने अपना स्टाफ भी हटा लिया है जिससे मवन खाली पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हस्तांतरण में देरी से मवन को क्षति या चोरी का खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि उनके पास पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी है इसलिए वे मवन लेने में आनाकानी कर रहे हैं। आमजनता का कहना है कि जब स्टाफ ही उपलब्ध नहीं है तो करोड़ों रुपये का मवन बनाने का कोई अर्थ नहीं निकलता। जनता का यह भी कहना है कि शासन द्वारा समय पर मवन तो बना दिया गया लेकिन आज भी क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हैं। यह लापरवाही न केवल शासन के धन का अपव्यय है बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य अधिकारों से भी खिलवाड़ है।

अज्ञात कारण से युवक

की अस्पताल पहुंचने के पूर्व मौत

अनूपपुर। रविवार को दोपहर कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ पिपेरिया गांव के 44 वर्षीय युवक की अज्ञात कारण से घर के पास ही बेहोश हो जाने पर ग्रामीणों एवं परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया जहां पहुंचने की पूर्व ही मृत्यु हो गई, घटना की सूचना पर जिला अस्पताल पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। घटना के संबंध में ग्रामीण एवं परिजनों ने बताया कि 44 वर्षीय झल्लू कोल पिता झगरू कोल जो पशु चिकित्सा विभाग अनूपपुर में पदस्थ है रविवार को दोपहर पिपेरिया गांव में अपने घर के पास बैठ रहा तभी अचानक अज्ञात कारण से बेहोश हो गया जिसे गांव के नागरिक संतोष पटेल अन्य ग्रामीणों एवं परिजनों के साथ अपनी कार में बेहोश स्थिति में झल्लू कोल को जिला चिकित्सालय ला कर इयूटी डॉक्टर से परीक्षण कराया परीक्षण पर डॉक्टर ने झल्लू कोल की अस्पताल पहुंचने के पहले ही मृत्यु हो जाने की बात बताते हुए घटना की जानकारी जिला अस्पताल पुलिसचौकी को दिए जाने पर पुलिस के द्वारा ग्रामीणों एवं परिजनों की उपस्थिति में मृतक के शव का पंचनामा कर पीएम कराने बाद अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को शव सौंप कर जांच की, मृतक की मृत्यु का वास्तविक कारण पीएम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट तौर पर पता चल सकेगा।

आज किसान न्याय यात्रा

और वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष



अनूपपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अनूपपुर जिले का एक दिवसीय दौरा 15 सितंबर को किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष न रमेश सिंह ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक दिवसीय दौरे पर अनूपपुर जिले में किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष सोमवार को सुबह 10 बजे भी नर्मद के दर्शन और पूजा-अर्चना से शुरू होगा। दोपहर 2 बजे पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजेन्द्रगाम में कार्यक्रमों की बैठक में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2-30 बजे जैतहरी में जिला कांग्रेस अनूपपुर द्वारा आयोजित किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शाम 4-15 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय अनूपपुर में होगा। जहां वह जनता से मुलाकात करेंगे और प्रक्रावर्ताओं को संबोधित करेंगे।

सरपंच-सचिव ने जनपद सदस्य से मिलकर कागज में बना दिया खेल मैदान

ग्राम उमरिया मे 'खेल मैदान' नहीं बल्कि बन रहा 'भ्रष्टाचार का मैदान'

इकार गए निकाली गई राशि, अमानत में खरानत का बड़ा मामला

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन उन्हें जरूरी संसाधनों का अभाव है। कमजोर आर्थिक स्थिति और संसाधनों की कमी के कारण इन प्रतिभाओं का सही विकास नहीं हो पाता। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण खेल मैदान योजना लागू की गई है। हालांकि, इस योजना का लाभ वास्तविकता में कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान तो बन गए हैं, लेकिन वे अधूरे हैं, वहीं कुछ जगहों पर तो खेल मैदान कागजों तक ही सीमित रह गए हैं और भ्रष्टाचार का शिकार हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत उमरिया में सामने आया है।

सरपंच व जनपद सदस्य ने किया खेला

जिले में ग्रामीणों को स्वस्थ बनाने के लिए बनाए जाने वाले खेल मैदानों की सही निर्माण के शुरूआत के साथ ही शुरू हुए भ्रष्टाचार से खराब होती दिख रही हैं। जिसका उदाहरण जिले के विकास खण्ड जैतहरी के ग्राम उमरिया में देखने को मिला। यहां



लगभग 6 लाख 50 हजार रुपये से बनने वाले खेल मैदान में सभी मानकों को दरकिनार कर कार्य चल रहा है। यहां खेल मैदान बनाने की जिम्मेदारी पंचायत को दी गई, लेकिन एक महिला जनपद सदस्य के साथ सरपंच व सचिव ने मिलकर अमानत में खरानत कर दिया, पंचायत ने पूरा खेल मैदान बनाया नहीं और खाते से पैसा निकाल लिया गया। आरोप है कि सरपंच, सचिव व जनपद सदस्य तीनों ने मिलकर खेल मैदान की राशि का बंदरबांट कर लिया है।

पंचायत ने लांची भ्रष्टाचार की सगी सीमा

जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां खेल मैदान बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार की सीमा लांच दी गई और जिम्मेदारों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। खेल मैदान में पंचायत के जिम्मेदारों ने लगभग चार लाख रुपये के भारी भरकम राशि का घोटाला किया है। जानकारी के मुताबिक खेल मैदान उमरिया के सरपंच व एक महिला जनपद सदस्य ने मिलकर बनाया है, उक्त कार्य के लिए सरकारी मद से

15वें वित्त में जनपद द्वारा 6 लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत हुआ है। खेल मैदान बनाने के लिए जिम्मेदारों द्वारा बाहर से मिट्टी लाकर डाल दी गई है वहीं रोलिंग कराना भी मुनासिब नहीं समझा गया। इसके अलावा मजदूरों को मजदूरी भुगतान न कर इनके द्वारा वेंडर को भुगतान किया गया है जो अपने आपमें बड़े घोटाले की ओर इंगित करता है। यहां कागजों में ही खेल मैदान का निर्माण हो गया, जबकि धरातल पर योजना के अनुसार कुछ भी नहीं दिखाई दिया।

भ्रष्टाचार की मेंट चढ़ा 'विकास'

उमरिया में विकास कार्यों में मनमाने तरीके से अनियमितता और अनुपयोगी कार्य कराके जहां सरकारी बजट को चूना लगाया जा रहा है, वहीं पंचायत प्रतिनिधि हर काम में कमाई के चक्कर में कायदे कानून ताक पर रखकर कायदे कानून के पालन से बेपरवाह हैं। उन्हें न जांच की चिंता है, न अधिकारियों का डर है। यहां पहले भी ऐसे तमाम काम कराए गए, जिनमें कमाई का रास्ता नजर आया। यहां तक कि कई अनुपयोगी काम भी करा दिए गए हैं, ऐसे तमाम निर्माण कार्य कराकर जिम्मेदारों ने अपना-अपना हिस्सा तो ले लिया पर ये निर्माण कार्य अनुपयोगी पड़े-पड़े बर्बादी की कगार पर हैं। मनरेगा के काम मशीनों से कराकर फर्जी मस्टर भरे जा रहे हैं।

डोला में भालू का आतंक, कई सूचना के बावजूद वन विभाग की नहीं टूट रही नींद

13 वर्षीय बच्ची पर हमले के बाद दहशत में वार्डवासी

हरिभूमि न्यूज राजनगर।

नगर परिषद डोला क्षेत्र में लगातार भालूओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन वार्डों में भालूओं के घुसने और लोगों पर हमला करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 4 का है, जहाँ रविवार सुबह करीब 4:45 बजे भालू ने 13 वर्षीय रागनी राजभर पर हमला कर दिया। घायल बच्ची को मनेन्द्राढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसके शरीर पर सात टांके लगे। फिलहाल उसका उपचार जारी है और परिवार भयभीत है।



रतजगा को मजबूर वार्डवासी

स्थानीय नागरिकों का कहना है, कि कई बार भालू रात में घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, और सामने आने पर हमला कर देते हैं। अब हालत यह है कि लोग अंधेरा होते ही घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि हम रोज डर के साये में जी रहे हैं, ना बच्चों को सुरक्षित छोड़ सकते हैं, ना खुद चैन से सो पाते हैं। नागरिकों ने कई बार वन विभाग के अधिकारियों और जिले के उच्च अधिकारियों को सूचना दी। यहाँ तक कि स्थानीय पत्रकारों ने भी बार-बार खबरों के माध्यम से प्रशासन को आगाह किया। इसके बावजूद वन विभाग सिर्फ आश्वासन देता रहा, लेकिन कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया।

वार्ड पार्श्व ने लिखा पत्र "जनता को बचाइए"

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

वार्ड क्रमांक 4 की पार्श्व श्रीमति प्रियंका सिंह ने वन विभाग को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि नगर मे शाम होते ही भालूओं का आतंक बढ़ जाता है जिससे हमारे वार्ड सहित समुचा डोला नगर भालू के डर से भयभीत है जिसे तत्काल पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए, ताकि नगर के लोगों की जान-माल की रक्षा हो सके। पार्श्व ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो जनता आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। गौरतलब है कि हर बार वन विभाग यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि "भालू छत्तीसगढ़ से आ रहा है", जबकि छत्तीसगढ़ का वन विभाग इसे मध्यप्रदेश का बता देता है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा का यह खेल आखिर कब तक चलेगा? जनता सवाल कर रही है कि प्रशासन कब जिम्मेदारी लेगा और कब शुरू होगा आदमखोर भालू का रेस्क्यू आपरेशन। स्पष्ट है कि डोला में वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही के कारण जनता दहशत में जी रही है। यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो स्थिति और भयावह हो सकती है।

इनका कहना है

भालू की संख्या ज्यादा है रेस्क्यू करने में दिक्कत होती है फिर भी हम रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी को सौंपेंगे जल्द ही कुछ न कुछ निराकरण किया जाएगा।

विपिन कुमार पटेल, वन मण्डलाधिकारी वन विभाग अनूपपुर

जिला स्तरीय मोगली विज प्रतियोगिता उत्कृष्ट विद्यालय अनूपपुर में संपन्न



विद्यार्थियों में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लगाव व्यक्त कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय मोगली प्रतियोगिता का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय अनूपपुर के विवेकानंद सभागार में 13 सितंबर को संपन्न हुआ। इस विज प्रतियोगिता में अनूपपुर जिले के चार विकास खंडों से 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का आयोजन वरिष्ठ वर्ग और कनिष्ठ वर्ग से किया गया। वरिष्ठ वर्ग में जैतहरी ब्लॉक से बालभारती विद्यालय जैतहरी के बालक और वालिका दोनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि कनिष्ठ वर्ग में केंद्रीय विद्यालय अनूपपुर के छात्र एवं कोतमा ब्लॉक शा. मा. विद्यालय बेसिक कोतमा की छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों ही वर्गों के प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी राज्य स्तरीय मोगली विज प्रतियोगिता के लिए पंच राष्ट्रीय अभ्यारण सिवनी के लिए दिनांक 26 अक्टूबर को रवाना होंगे जहां पर 27 से 29 अक्टूबर

तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस विज प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संरक्षण को बचाने एवं मध्यप्रदेश से सम्बन्धित प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को सवाल जिला विजय मास्टर शिवदत्त पाण्डेय एवं हेतुराम साहू द्वारा पूछे गए जिसका उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। इस दौरान राज्य स्तरीय विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिता दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अनूपपुर तुलाराम आर्मा एवं शा.उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर के वरिष्ठ व्याख्याता राकेश कुमार बांधवा के द्वारा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। अपने अतिथि उद्बोधन में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यार्थियों को

विभिन्न मांगों को लेकर आज बिजली आउटसोर्स कर्मों कलेक्टर, सांसद व विधायकों को सौंपेंगे ज्ञापन

मांगें नहीं माने जाने पर धनतेरस से दीपावली तक काम बंद आंदोलन की चेतावनी

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

मप्र के 45 हजार बिजली आउटसोर्स कर्मियों ने धनतेरस से दीपावली तक प्रस्तावित काम बंद आंदोलन को लेकर म.प्र. के सभी 55 जिलों के कलेक्टर, सांसद, विधायकों को ज्ञापन सौंपने संबंधी अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव, महामंत्री दिनेश सिंसोदिया एवं भदौरिया के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ज्ञापन में प्रमुख मांगें हैं जिनमें म.प्र. की सभी छह बिजली कंपनियों में जो निकट भविष्य में करीब 50 हजार रिक्त पदों को मौजूदा एवं सेवा से पृथक अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों की विभागीय परीक्षा लेकर उसी प्रकार भरा जाए जैसे ठेका प्रथा लागू होने से पहले पिछले 50 सालों में बिजली डेली वेजेस मास्टर कर्मियों को कच्चे से पक्का किया जाता रहा। इस 50 हजार की भर्ती के बाद भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर 50 प्रतिशत पद ऊर्जा विभाग राजपत्र के जरिए बिजली आउटसोर्स कर्मियों को आरक्षित करे व छोटे



पद बना कर रेगुलर करें। तमिलनाडू की तर्ज पर मप्र में मुख्य कार्य सीधी भर्ती से कराए। मप्र के राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद राजपत्र क्रमांक 494 दिसम्बर 2020 के मुताबिक बोनस 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया उसे उसी तिथि से लागू कर 57 माह की 11.67 प्रतिशत की दर से बोनस एरियर राशि हर ठेका श्रमिक को दी जाए, केंद्र सरकार के आउटसोर्स कर्मियों के बराबर मप्र के आउटसोर्स को न्यूनतम वेतन दें, पिछले 20 सालों के दौरान म. प्र. में मिनिमम वेजेस 5 साल की जगह हर बार 9 साल में रिवाइज हुआ, इस घाटे की भरपाई एडिशनल वेजेस देकर की जाए। भाजपा विधानसभा चुनावी संकल्प पत्र के पृष्ठ 81 पर अमल कर आउटसोर्स को संविदा का

दर्जा व संविदा समान सुविधा दें। मप्र में ठेकेदारी कल्चर समाप्त कर आउटसोर्स रिफॉर्म नीति बनाई जाए, बिजली कंपनी का निजीकरण नहीं किया जाए। ठेकेदार व बिचौलियों को हटाकर हरियाणा, आंध्र प्रदेश व उप्र राज्य की तर्ज पर मप्र आउटसोर्स सेवा निगम बनाए, 5 वर्ष से अधिक अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों को उड़ीसा राज्य की तर्ज पर एक हजार रुपए अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ता दें। कम्प्यूटर व सब स्टेशन संयंत्र ऑपरेंटर को कुशल की जगह उच्च कुशल श्रेणी का वेतन दिया जाए, रात्रि पाली में काम करने पर रात्रि भत्ता दें, 10 प्रतिशत आउटसोर्स हेल्पर की जगह सभी आउटसोर्स लाइन हेल्पर, विद्युत सहायक, संयंत्र व सब स्टेशन ऑपरेंटरों को जोखिम भत्ता दें। वर्ष 2006 में ठेका प्रथा प्रारंभ होने से लेकर अब तक विद्युत दुर्घटना में मरे व विकलांग ठेका श्रमिकों के परिजनों को बिना शर्त मुआवजा दें एवं मौजूदा मुआवजा राशि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाए एवं विद्युत दुर्घटना मृतक के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाये।

कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेने पर होंगे विवश

ज्ञापन में कहा गया कि नियमित कर्मियों की भांति आउटसोर्स कर्मों 62 वर्ष तक सेवा में रखे जाएं, पूर्व में या आंदोलन के दौरान हटाए गए आउटसोर्स कर्मों बिना शर्त वापिस रखे जाएं। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मों को एक वर्ष में



जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह ने किया जिले की सीमा के अंतिम पंचायत का दौरा पंचायत ने ग्रामीणों की सुनी समस्या

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले के अंतिम छोर की ग्राम पंचायत मुडुधोवा में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति रमेश सिंह ने शनिवार को दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएँ सुनीं और उनके समाधान के लिए तत्काल निर्देश दिए। बैठक में ग्रामीणों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे अध्यक्ष के समक्ष रखे। इनमें कैलाश घाट से बंजारटोला तक ग्रैवल मार्ग निर्माण, ग्राम बंजारटोला में विद्युतीकरण, ग्राम मुडुधोवा में कोमल यादव के घर से स्कूल तक पीसीसी रोड निर्माण, सुधा द्विवेदी के घर से मेन रोड तक पीसीसी रोड, हरिजन मोहल्ले में पीसीसी रोड, ब्रह्मण मोहल्ले में सांस्कृतिक मंच निर्माण, नल-जल योजना की पानी टंकी की मरम्मत एवं प्राथमिक विद्यालय मुडुधोवा को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन जैसी मांगें प्रमुख रही। जिला पंचायत अध्यक्ष ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत सज्ञान लेने और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की मांगों और शिकायतों का त्वरित समाधान ही मेरी प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तभी संभव है जब हम जनता की समस्याओं को प्रत्यक्ष सुनकर उनके निराकरण की दिशा में ठोस कदम उठाएँ। बैठक में जनपद अनूपपुर सीईओ रवि ग्वाल, समाजसेवी एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डी.एस. राव, जिला कांग्रेस के महामंत्री नरेन्द्र सिंह, कांग्रेस नेत्री श्रीमती नूपुर चटर्जी, सरपंच मान कुमार सिंह, सचिव राजुराम जोशी, देवगांव सरपंच किरण सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के इस दौर को सराहते हुए कहा कि उनके सीधे संवाद से विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और समस्याओं के समाधान की राह आसान होगी।

मां का दरबार सजने के पूर्व तैयारियां जोरों पर, मूर्तिकार मूर्तियों को दे रहे अंतिम रूप

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर/कोतमा। नवरात्र शुरू होने में आठ दिन शेष बचे हैं। मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को मध्य रूप देने में जुटे हैं। कोतमा नगर में मूर्तिकार पिछले बीस वर्षों से मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा की स्थापना के लिए समितियों की ओर से मूर्तियों की बुकिंग भी प्रारंभ हो गई है। 22 सितम्बर से शुरू होने वाले नवरात्र पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मां दुर्गा की प्रतिमाओं को मध्य रूप देने के लिए मूर्तिकार दिन-रात काम में जुटे हुए हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि वह स्वयं मूर्ति बना रहे हैं। समय से लोगों को मूर्तियां देने के लिए काम जोरों पर किया जा रहा है। नगर में शारदीय नवरात्र पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। नवरात्र पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। दुर्गा पूजा समिति के सदस्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। दुर्गा प्रतिमा तैयार करने में मूर्तिकार और पूजा पंडाल को आकर्षक बनाने में समिति के सदस्य लगे हुए हैं। शारदीय नवरात्र में शक्ति की अष्टिष्ठात्री मां दुर्गा की पूजा होगी। नगर में आकर्षक पंडाल बनाने की तैयारी चल रही है। समिति के सदस्य दुर्गा प्रतिमाओं की बुकिंग किए हैं। उत्साह से चल रही पूजा पंडाल सजाने की तैयारियां- नगर में शारदीय नवरात्र पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह है। नगर में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर दुर्गा



प्रतिमा स्थापित करने के लिए पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। नगर के मठ मंदिरों में साफ सफाई रंग रोगन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मूर्तिकार रमेश पाल ने बताया कि इस बार उन्होंने मां दुर्गा की 140 छोटी-बड़ी प्रतिमा मिलकर बनाई है। 15 फीट से लेकर 10 फीट तक की प्रतिमा का निर्माण किया है। 5000 से 35000 हजार कीमत रखी है। उन्होंने बताया कि इस बार सामग्रियों के दाम भी बढ़े हैं वह सजावट का सामान कोलकाता से लेकर आते हैं और स्थानीय स्तर पर मिट्टी बांस पैरा सुतली सहित अन्य सामान खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि वह 30 वर्षों से कोतमा में मुखर्जी चौक पर आकर प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्रि पर्व को 8 दिवस शेष बचे हैं जिसको लेकर वह स्वयं एवं अपने साथी मूर्तिकारों के साथ दिन-रात प्रतिमा में रंग रोगन का कार्य करते हैं जुटे हुए हैं। मूर्तिकार गोपाल पाल ने बताया कि वह कोलकाता से आकर कोतमा में मूर्ति बनाने का कार्य लगभग 10 वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने दुर्गा जी की छोटी-बड़ी प्रतिमा मिलाकर कुल 190 प्रतिमा का निर्माण किया है। जिसकी कीमत 3000 से लेकर 30000 रूपया तक रखी है। उन्होंने बताया कि 2 फीट से लेकर 10 फीट तक की प्रतिमा का निर्माण किया है। सामानों की रेट भी बढ़े हैं जिसके कारण उन्हें सही दाम भी नहीं मिल पाते हैं।